

प्रेषक,

सुरेन्द्र सिंह रावत
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
देहरादून।

पेयजल अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक 25 मई 2011

विषय: चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 में जिला योजना के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (सामान्य) के अंतर्गत जनपद देहरादून की ग्रामीण पेयजल योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

जिला योजना की न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (सामान्य) के अन्तर्गत ग्रामीण पेयजल योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु शासनादेश संख्या 495 / उन्तीस(2)/11-2(03पे0)/2011 दिनांक 19 अप्रैल 2011 द्वारा अवमुक्त धनराशि 3916.69 लाख के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिला योजना की न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (सामान्य) के अन्तर्गत जनपद देहरादून हेतु निर्धारित परिव्यय 372.98 लाख के अवशेष ₹ 30.00 लाख (तीस लाख मात्र) की धनराशि श्री राज्यपाल महोदय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (सामान्य) के अंतर्गत जनपद देहरादून की जिला योजना की सामान्य श्रेणी की ग्रामीण पेयजल योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 में व्यय हेतु आपके निर्वर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उपरोक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण उत्तराखण्ड पेयजल निगम के जनपद देहरादून के अधिशासी अभियन्ता/नोडल अधिकारी के हस्ताक्षरयुक्त तथा जिलाधिकारी देहरादून के प्रतिहस्ताक्षरित बिल जनपद देहरादून के कोषागार में प्रस्तुत करके वास्तविक आवश्यकतानुसार किशतों में पूर्व स्वीकृत धनराशि का पूर्ण उपयोग अथवा 80 प्रतिशत धनराशि के उपयोग के उपरान्त ही किया जायेगा। पूर्व में स्वीकृत समस्त धनराशि का उपयोग होने के उपरान्त आवंटित धनराशि का आवश्यकतानुसार आहरण कर सकते हैं।

3- कार्य की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता अथवा इस स्तर का अधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा।

4- कराये जाने वाले कार्यों पर वित्त(वे0आ0-सा0नि0) अनुभाग-7 के शासनादेश संख्या 163/XXVII(7)/2007, दिनांक 22.05.08 के अनुसार सेन्टेज प्रभार अनुमन्य होगा।

5- व्यय करते समय बजट मेनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 का अनुपालन किया जायेगा।

6- स्वीकृत धनराशि का व्यय प्रथमतया चालू योजनाओं पर किया जायेगा तथा चालू योजनायें शेष न होने पर ही नये कार्यों पर योजनावार विवरण उपलब्ध कराने पर शासन की अनुमति के उपरान्त ही धनराशि व्यय की जायेगी।

7- उक्त स्वीकृत धनराशि से जिला योजना में अनुमोदित ग्रामीण पेयजल योजनाओं का क्रियान्वयन उत्तराखण्ड पेयजल निगम द्वारा किया जायेगा।

8— जनपदवार स्वीकृत धनराशि के योजनावार आवंटन की सूचना 2 सप्ताह के अन्दर शासन को अवश्य उपलब्ध करा दी जाय, जिसमें लाभान्वित होने वाली एन0सी0 तथा पी0 सी0 बस्तियों का विवरण अवश्य स्पष्ट रूप से अंकित किया जाय।

9— स्वीकृत धनराशि ऐसी योजनाओं पर कदापि व्यय न की जाय, जिसके संबंध में तकनीकी स्वीकृति प्राप्त नहीं हैं अथवा जो विवादग्रस्त है।

10— व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और फाईनेन्शियल हैंडबुक नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अंतर्गत शासकीय अथवा सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हों, उसमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। निर्माण कार्यों पर व्यय करने से पूर्व आगणनों/पुनरीक्षित आगणनों पर सक्षम प्राधिकारी की तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

11— स्वीकृत धनराशि से वही कार्य किया जायेगा जो जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति द्वारा अनुमोदित हो और जनपदवार आवंटित प्लान परिव्यय के अन्तर्गत हों तथा जिला अनुश्रवण समितियों द्वारा अनुमोदित परिव्यय से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

12— स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 30.06.2011 तक पूर्ण उपयोग करके इसकी वित्तीय/भौतिक प्रगति एवं उपयोगिता प्रमाणपत्र शासन को प्रस्तुत किया जायेगा।

13— ₹0 50.00 लाख तक की योजनाओं की वित्तीय स्वीकृति जिलाधिकारी स्तर से जारी की जायेगी तथा ₹0 50.00 लाख से अधिक की स्वीकृति मण्डलायुक्त के अनुमोदन के उपरान्त जारी की जायेगी। स्वीकृतियों के प्रस्ताव जनपद/मण्डल स्तरीय नोडल अधिकारी द्वारा तैयार कर अर्थ एवं संख्या विभाग के जनपद/मण्डलीय कार्यालय को उपलब्ध कराये जायेगे, जो इन प्रस्तावों को परीक्षण के उपरान्त जिलाधिकारी एवं मण्डलायुक्त को प्रस्तुत करेंगे।

13— उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 के अनुदान संख्या -13 के लेखाशीर्षक-4215-जलपूर्ति तथा सफाई 01-जलपूर्ति-आयोजनागत-102-ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम-91-जिलायोजना-01-ग्रामीण पेयजल तथा जलोत्सारण योजना- 35-पूँजीगत परिसवमत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामें डाला जायेगा।

14— यह शासनादेश राज्य योजना आयोग के शासनादेश संख्या 624/जि0यो0/रा0यो0आ0/मु0स0/2008, दिनांक 24.03.08 तथा वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 267/XXVII(1)/2008, दिनांक 27.03.08 में उल्लिखित निर्देशानुसार निर्गत किया जा रहा है।



भवदीय,

(सुरेन्द्र सिंह रावत)
अपर सचिव